उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील सं. 9/2008

आयुक्त,

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ..... अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स उत्तरांचल आयरन एंड इस्पात लिमिटेड .....प्रतिवादी।

श्री शोभित सहारिया, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए

श्री P.R. मलिक, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए

निर्णय

कोरमःमाननीय बारीन घोष, मुख्य न्यायाधीश

माननीय वी.के. बिस्ट, न्यायाधीश

बारीन घोष, मुख्य न्यायाधीश (मौखिक)

आबकारी विभाग ने प्रतिवादी को यह तर्क देते हुए एक नोटिस जारी किया जिसमे तर्क दिया गया कि चूंकि प्रतिवादी की क्षमता का विस्तार किसी अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2003 के तहत छूट का हकदार नहीं है। 10 जून, 2003 की अधिसूचना के संबंध में, 21 जनवरी, 2004

को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था। उक्त स्पष्टीकरण द्वारा, 7 जनवरी, 2003 की अधिसूचना में उपयोग किए गए 'पर्याप्त विस्तार' शब्द को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया था, जिसके बाद 10 जून, 2003 की अधिसूचना में उपयोग किया गया थाः-

(ए) किसी मौजूदा इकाई की स्थापित क्षमता में कम से काम २५% की वृद्धि अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी की स्थापना का परिणाम होना चाहिए। अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के अलावा स्थापित क्षमता में कोई भी वृद्धि "पर्याप्त विस्तार" के तहत छूट के लाभ के लिए योग्य नहीं होगी।

(बी) चूंकि पर्याप्त विस्तार को स्थापित क्षमता में २५% या उससे अधिक की वृद्धि के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, इसलिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश का मूल्य पर्याप्त विस्तार को परिभाषित करने के लिए मानदंड नहीं है। जब तक संयंत्र और मशीनरी की अतिरिक्त स्थापना के परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता में 25% से कम की वृद्धि नहीं होती है या संयंत्र और मशीनरी में निवेश का मूल्य पर्याप्त विस्तार के मानदंडों को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

(ग) पर्याप्त विस्तार करने के लिए पुरानी मशीनरी के उपयोग पर कोई रोक नहीं है, जब तक कि यह मौजूदा स्थापित क्षमता को 25% से

कम नहीं बढ़ाता है। संयंत्र और मशीनरी की अतिरिक्त स्थापना के माध्यम से स्थापित क्षमता में 25% से कम की वृद्धि प्रासंगिक है।

(घ) पर्याप्त विस्तार शब्द को संयंत्र और मशीनरी के मूल या मूल्यह्रास मूल्य के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया गया है। संतुष्ट होने के लिए एकमात्र मानदंड अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी के साथ कम से कम 25% द्वारा स्थापित क्षमता में वृद्धि मात्र है।

(ङ) आधुनिकीकरण में या मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए संयंत्र और मशीनरी में अतिरिक्त निवेश, जब तक कि यह स्थापित क्षमता में 25% या उससे अधिक की वृद्धि नहीं करता है, पर्याप्त विस्तार के समान नहीं होगा।"

2. प्रतिवादी ने कारण दर्शाओ के लिए अपना जवाब दाखिल किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी 10 जून, 2003 की अधिसूचना के साथ 7 जनवरी, 2003 की अधिसूचना के संदर्भ में छूट का हकदार नहीं है। तदनुसार, प्रतिवादी ने अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया और उसके समक्ष हारने के बाद न्यायाधिकरण के समक्ष गया। न्यायाधिकरण ने नोट किया, जिस पर कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है, कि आयुक्त, उत्पाद शुल्क ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (चक्रवृद्धि शुल्क योजना) की धारा 3-ए के अंतर्गत प्रतिवादी की स्थापित क्षमता का निर्धारण किया, और जब

प्रतिवादी ने दावा किया कि उसने अपनी स्थापित क्षमता में वृद्धि की है, तो उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता ने पाया कि प्रतिवादी की स्थापित क्षमता में उस की स्थापित क्षमता के २५% से अधिक की वृद्धि की गई है। न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि उक्त सर्वेक्षक ने बताया कि क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रतिवादी ने अपनी मौजूदा भट्टी की लंबाई 70 फुट से बढ़ाकर 120 फुट कर दी। न्यायाधिकरण ने पाया कि पहले की मोटर को भारी मोटर से बदल दिया गया था। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि पहले के गियरबॉक्स को भी बदल दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण के इन निष्कर्षों पर कोई विवाद नहीं है। ऐसा ही पाते हुए, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि पहले से मौजूद मशीनरी में संशोधन करके, चूंकि स्थापित क्षमता में 25% से अधिक की वृद्धि की गई है, इसलिए प्रतिवादी 10 जून, 2003 के आदेश के साथ 7 जनवरी, 2003 के सरकार के आदेश के तहत लाभों का हकदार था।

3. वर्तमान अपील में, राजस्व द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मौजूदा भट्टी को संशोधित किया गया था और मौजूदा मोटर और गियरबॉक्स को बदल दिया गया था और तदनुसार, स्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया था। हम महसूस करते हैं कि 21 जनवरी, 2004 के बोर्ड के परिपत्र को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। परिपत्र पर एक नज़र डालें, जिससे यह स्पष्ट हो

जाएगा कि अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी की स्थापना द्वारा 25% क्षमता की तथ्यात्मक वृद्धि पर जोर दिया गया था। इस तरह के अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी पुरानी हो सकती है, जिसका मूल्य न्यूनतम हो सकता है, लेकिन स्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी को तैनात किया जाना चाहिए। इसने यह नहीं कहा कि उत्पादन की मौजूदा लाइन और उसके लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण बने रहने चाहिए और नए संयंत्र और मशीनरी से युक्त उत्पादन की एक अलग लाइन, जिसमें मौजूदा की 25% क्षमता हो, को लाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, 'अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी' शब्द का उपयोग करते समय, इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि मौजूदा संयंत्र और मशीनरी बनी रहे। यह माना गया था कि संयंत्र और मशीनरी के रूप में कुछ अतिरिक्त लाया जाना चाहिए, जो पुरानी हो सकती है, और जिसके द्वारा, क्षमता का विस्तार किया गया है। तत्काल मामले में, मौजूदा भट्टी की लंबाई बढ़ा दी गई थी। भट्टी, जो अस्तित्व में थी, वह भट्टी नहीं है, जो अब अस्तित्व में है। भट्टी, जो अब अस्तित्व में है, एक अतिरिक्त संयंत्र है। यह सच है कि अतिरिक्त संयंत्र, भट्टी के रूप में, एक पुराना संयंत्र है जिसे उसके संशोधन द्वारा विनिर्देशन के लिए बनाया गया है, लेकिन 21 जनवरी, 2004 के स्पष्टीकरण परिपत्र में इसकी कोई रोक नहीं है। गियरबॉक्स और मोटर को बदल दिया गया है। ये अतिरिक्त यंत्र हैं। परिपत्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी

मशीनरी, अतिरिक्त मशीनरी होने के आदेश, उन के अतिरिक्त होनी चाहिए, जो मौजूद हैं। उक्त स्पष्टीकरण, जिसमें "आधुनिकीकरण में संयंत्र और मशीनरी में अतिरिक्त निवेश" शब्दों का भी उपयोग किया गया है, परिपत्र के दूसरे भाग के साथ पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट करता है कि इसमें उल्लिखित अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी, मौजूदा के अलावा नहीं है, बल्कि विनिर्माण प्रक्रिया में लाए गए कुछ नए को दर्शाता है, जो बदले में क्षमता को बढ़ाता है। यदि ऐसा है, तो प्रतिवादी के बजाय, स्वयं अपनी भट्टी की लंबाई बढ़ाते हुए, उसी का निपटान कर सकता है और विक्रेता द्वारा उसकी लंबाई बढ़ाने के पश्चात उसी वस्तु को अपने विक्रेता से खरीद सकता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के आदेश, परिपत्र में "आधुनिकीकरण में संयंत्र और मशीनरी में अतिरिक्त निवेश" शब्दों को शामिल किया गया है।

4. तदनुसार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान अपील में आक्षेपित न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

(वी. के. बिस्ट, न्यायाधीश) **(बारीन घोष, मुख्य न्यायाधीश)**

22.12.2010 22.12.2010

जी